श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

969. श्री आल मोहम्मद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा क्या है और 1981–1991 की अवधि के दौरान श्रमिकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) वर्ष 1991 में ग्रामीण शहरी संगठित - असंगठित और लघु उद्योग क्षेत्रों में पृथक्-पृथक रूप से नियुक्त किये गये श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में पृथक-पृथक रूप से नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्ष 1992–93 के दौरान ग्रामीण, शहरी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संभावित संख्या कितनी है और 31 मार्च, 1994 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति किस हद तक हो गयी है ; और

(ङ) रोजगार की वर्तमान विकास दर क्या है और वर्ष 1992–97 तथा 1997–2000 में पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कितनी विकास दर अपेक्षित है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) अलग-अलग वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किये गये कामगारों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । 1991 की जनगणमा के अनुसार, अभी तक उपलब्ध आंकड़े श्रम बल से संबंधित हैं, अर्थात् मुख्य एवं सीमांत कामगारों की श्रेणियों में कामगारों की संख्या । कुल संख्या 314.13 मिलियन थी। इनमें से 49.03 मिलियन ग्रामीणएवं 635.10 मिलियन शहरी क्षेत्रों से थे। 1981–91 के दशक के दौरान कामगारों की विकास दर 2.38% प्रति वर्ष थी। इस जनगणना में, संगठित असंगठित एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में पृथक-पृथक रूप से नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

1991 की जनगणनानुसार वर्ष 1991 में मुख्य कामगारों का क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र		मुख्य कामगारों की संख्या (मिलियन में)
i.	कृषक . .	110.70
ii.	कृषि श्रमिक .	74.60
iii.	पशुधन, वानिकी, मत्स्य, शिकार एवं वृक्षारोपण, फलोद्यान एवं संबद्ध कार्यकलाप	6.04
iv.	खनन एवं उत्खनन	1.75
v.	विनिर्माण, प्रक्रियान्वयन, सर्विसिंग तथा मरम्मत .	
	(क) घरेलू उद्योग में	6 30
	(ख) घरेलू उद्योगों के अलावा	21.87
vi.	संरचना .	5.54
vii.	व्यापार तथा वाणिज्य .	21.30
viii.	परिवहन, भंडारण तथा संचार .	8.02
ix.	अन्य सेवाएं .	29.31
	(कुल i–ix) .	285.93

नोट :— जम्मू व काश्मीर में, 1991 की जनगणना नहीं हुई थी।

वर्ष 1992 एवं 1993 के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

आठवीं योजना के दस्तावेज में उपलब्ध अनुमान के अनुसार योजना के 1992–99 के दौरान वृद्धि की दर एवं स्वरूप में 43 मिलियन तक और अधिक रोजगार के अवसरों की परिकल्पना की गई है। इन अनुमानों को ग्रामीण, शहरी संगठित व असंगठित क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। वर्ष 1992–94 के दौरान, लगभग 12.42 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं। योजना आयोग के अनुमानानुसार, योजना के पहले तीन वर्षों में रोजगार की विकास दर 2.12% प्रति वर्ष रही है। 1997 तक पूर्व रोजगार की स्थिति के लिए पांच वर्षों में 1992–97, औसतन 3.6% प्रतिवर्ष रोजगार विकास दर की जरूरत होगी, तथा 2002 तक पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए दस वर्ष की अवधि, 1992–2002 के दौरान औसतन 2.6 से 2.8% प्रति वर्ष रोजगार विकास दर की आवश्यकता होगी।

Determination of majority Status of trade unions through secret ballot

970. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI G. Y. KRISHNAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the recent Supreme Court judgement on the question of determination of majority union through secret ballot;

(b) if so, what is the reaction of the government on this question as it determines the collective bargaining in an industry|unit|establishment;

(c) whether any proposal to call an immediate meeting of State Labour Ministers|State Labour Secretaries Conference to take steps to implement the SC decision;

(d) will Government convene the meeting of Indian Labour Conference to determine the reaction of the Central Trade Unions on this issue; and

(e) if the answer to (c), (d) and (e) are in the negative, what other steps are being proposed to improve industrial peace in the country?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) Under the existing procedure, verification of membership of unions is conducted under the Code of Discipline ratified by the Indian Labour Conference in 1958. Subject to mutual consent between employers and the trade unions concerned, the verification can also be conducted through secret ballot. The judgement of the Hon'ble Supreme Court laying down guidelines and procedures for conducting secret ballot is confined to Food Corporation of India, based on mutual consent between the unions and FCI management.

(c) The Chief Labour Commissioner (Central) has already initiated action to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court. There is no need, therefore, to convene a Conference of State Labour Ministers| Secretaries to implement the Supreme Court decision

(d) There is no such proposal under the consideration of the Government.

(e) Government have taken several initiatives for sustained growth of harmonious industrial relations.

GNP and GDP in Gujarat and Maharashtra

971. SMT. CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the latest details regarding Gross National product and